Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University

(Accredited A++ by NAAC)

University in News on 24 June 2024

Dainik Jagran Page - 06

मूल्यांकन भवन का आज शिलान्यास करेंगी कुलाधिपति

गोरखपुर: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल सोमवार को नए परीक्षा मूल्यांकन भवन का शिलान्यास और सेंसस डाटा रिसर्च वर्क स्टेशन का आनलाइन शुभारंभ करेंगी। कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने बताया कि विश्वविद्यालय में मूल्यांकन के लिए 8.2 करोड़ रुपये की लागत से नया परीक्षा मूल्यांकन भवन बनने जा रहा है। प्राचीन इतिहास विभाग के पश्चिमी में 13 हजार वर्गफीट जमीन में इसका निर्माण किया जाएगा। इसका 75 प्रतिशत धन राज्य सरकार और 25 प्रतिशत विश्वविद्यालय देगा। इसे 18 माह में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए शासन से धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि यह भवन एसी एवं अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। सेंसस डाटा रिसर्च वर्क स्टेशन को विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी के साइबर लाइब्रेरी में स्थापित किया जाएगा। इस संदर्भ में 24 जून को कुलपति प्रो. पूनम टंडन व जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक शीतल वर्मा के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर भी किया जाएगा।

Amar Ujala Page - 07

कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल आज करेंगी नए मूल्यांकन भवन का शिलान्यास

संवाद न्यूज एजेंसी

गोरखपुर। गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल सोमवार को नए परीक्षा मूल्यांकन भवन का शिलान्यास और सेंसस डाटा रिसर्च वर्क स्टेशन का ऑनलाइन शुभारंभ करेंगी।

कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने बताया कि विश्वविद्यालय में मूल्यांकन के लिए 8.2 करोड़ रुपए की लागत से नया परीक्षा मूल्यांकन भवन बनने जा रहा है। प्राचीन इतिहास विभाग के पश्चिम में 13 हजार वर्गफीट जमीन में इसका निर्माण किया जाएगा। इसका 75 प्रतिशत धन राज्य सरकार और 25 प्रतिशत विश्वविद्यालय देगा। इसे 18 माह में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए शासन से धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। यह भवन एसी एवं अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा।

सेंसस डाटा रिसर्च वर्क स्टेशन का भी शुभारंभ करेंगी कुलाधिपति

सेंसस डाटा रिसर्च वर्क स्टेशन को विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी के साइबर लाइब्रेरी में स्थापित किया जाएगा। इस संदर्भ में 24 जून को कुलपति प्रो. पूनम टंडन व जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक शीतल वर्मा के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर भी किया जाएगा।

72 कॉलेजों ने नहीं दिया ब्योरा, खतरे में संबद्धता

डीडीयू : इन कॉलेजों में शुल्क में अनियमितता की आशंका, तीन वर्षों में कम धन जमा होने के मिले हैं संकेत

संवाद न्यूज एजेंसी

गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध 72 कॉलेजों ने पिछले तीन वर्षों में छात्रों और जमा शुल्क का डाटा नहीं दिया है। विश्वविद्यालय ने इन्हें छठवीं बार नोटिस देकर 26 जून तक ब्योरा उपलब्ध कराने के लिए कहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि इसे नहीं जमा किया गया तो संबद्धता खत्म की जा सकती है।

विश्वविद्यालय को पिछले तीन वर्षों में कॉलेजों की ओर से जमा किए गए शुल्क में वित्तीय अनियमितता के संकेत मिले हैं। इसके बाद ही संबद्ध कॉलेजों को छह अप्रैल को पत्र लिखकर सत्र 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में विभिन्न मद में जमा किए धन का विस्तृत ब्योरा 15 अप्रैल तक मांगा गया था। दूसरा नोटिस 16 अप्रैल, तीसरी 27 अप्रैल, चौथा सात मई, पांचवां नोटिस 15 मई को दिया गया। अब छठवीं बार नोटिस 22 जून को दिया गया है। विवरण नहीं देने वाले 72 कॉलेजों से 26 जून तक ब्योरा मांगा गया है।

कई अनुदानित कॉलेजों ने भी नहीं दिया ब्योरा : जिन 72 कॉलेजों ने शुल्क का ब्योरा नहीं दिया है, उसमें सेल्फ फाइनेंस के साथ-साथ अनुदानित कॉलेज भी शामिल हैं। सभी कॉलेजों से

कॉलेजों से पिछले तीन वर्षों में जमा की गई धनराशि का ब्योरा मांगा गया था। इसमें से 269 कॉलेजों ने जानकारी उपलब्ध करा दी है। बाकी बचे 72 कॉलेजों को छठवीं बार रिमाइंडर भेजकर 26 जून तक ब्योरा मांगा गया है। इसके बाद भी यदि इन्होंने ब्योरा नहीं दिया तो इन कॉलेजों में विद्यार्थियों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। - प्रो. शांतनु रस्तोगी, कुलसचिव

किस सत्र में कक्षा यूजी, पीजी, वार्षिक, सेमेस्टर, सीबीसीएस में कितने विद्यार्थी थे? कितने छात्र संस्थागत व कितने व्यक्तिगत थे? जमा धनराशि, चालान संख्या (साक्ष्य सहित), ट्रांजेक्शन का माध्यम (साक्ष्य सहित) मांगा गया है। कॉलेजों से मिली रिपोर्ट के आधार पर मिलान किया जाना है। अभी तक मिले डाटा का मिलान शुरू भी हो चुका है।

Hindustan Page - 02

पांच बार नोटिस के बाद भी कॉलेजों ने नहीं दिया जमा धन का ब्योरा

लापरवाह 72 कॉलेजों को छठा नोटिस जारी

डीडीयू

- छात्रों के सापेक्ष तीन वर्षों में कम धन जमा होने के मिले हैं साक्ष्य
- जवाब नहीं देने पर प्रवेश प्रतिबंधित करने की दी गई है चेतावनी

गोरखपुर, निज संवाददाता। शुल्क में हेरफेर की जांच कर रहे डीडीयू प्रशासन ने एक बार फिर कॉलेजों को नोटिस जारी किया है। ब्योरा नहीं देने वाले 72 कॉलेजों को छठवीं बार नोटिस जारी की गई है। डीडीयू की नोटिस पर अब तक 269 कॉलेजों ने छात्रों के सापेक्ष जमा धन का ब्योरा दे दिया है। डीडीयू ने चेताया है कि ब्योरा नहीं देने वाले कॉलेजों में सत्र 2024-25 में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। सम्बद्धता व अन्य आवेदनों पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

आपके अपने अखबार 'हिन्दुस्तान' ने 12 अप्रैल के अंक में 'डीडीयू को शुल्क में गड़बड़ी का शक! जांच के आदेश' शीर्षक के साथ इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर में बताया गया था कि डीडीयू में कॉलेजों द्वारा परीक्षा व विभिन्न मद में जमा हुए शुल्क में वित्तीय अनियमितता के संकेत मिले हैं। आशंका जताई गई थी कि छात्रों के सापेक्ष जितना धन जमा होना चाहिए था, उतना प्राप्त नहीं हुआ है।

सम्बद्ध कॉलेजों से 6 अप्रैल को पत्र लिखकर सत्र 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में विभिन्न मद में जमा किए धन का विस्तृत ब्योरा 15 अप्रैल तक मांगा गया था। उसके बाद चार बार रिमाइंडर दिया गया। विवरण नहीं देने वाले 72 कॉलेजों को पांचवीं बार रिमाइंडर भेजते हुए 26 जून तक ब्योरा मांगा गया है।

अब तक 269 कॉलेजों ने पिछले तीन वर्षों में जमा की गई धनराशि का ब्योरा दिया है। शेष 72 कॉलेजों को छठवीं बार रिमाइंडर भेजकर 26 जून तक ब्योरा मांगा गया है। ब्योरा नहीं देने पर कॉलेजों में प्रवेश रोक दिया जाएगा। - प्रो. शांतनु रस्तोगी, कुलसचिव, डीडीयू

कॉलेजों से मांगा गया है ये विवरण

किस सत्र में कक्षा यूजी, पीजी, वार्षिक, सेमेस्टर, सीबीसीएस में कितने विद्यार्थी थे? कितने छात्र संस्थागत व कितने व्यक्तिगत थे? जमा धनराशि, चालान संख्या (साक्ष्य सहित), ट्रांजेक्शन का माध्यम (साक्ष्य सहित) जमा करना है। कॉलेजों से मिली रिपोर्ट के आधार पर एक-एक डाटा का जमा करने की टाइमिंग के हिसाब से मिलान होगा।

कब-कब दी गई नोटिस : ब्योरा देने के लिए पहली बार 6 अप्रैल को नोटिस दी गई। दूसरी नोटिस 16 अप्रैल को, तीसरी नोटिस 27 अप्रैल को, चौथी 7 मई को, पांचवीं नोटिस 15 मई को दी गई। अब छठवीं नोटिस 22 जून को दी गई है। ब्योरा 26 जून तक कॉलेजों को देना है।

कुलाधिपति आज करेंगी मूल्यांकन भवन का शिलान्यास

गोरखपुर। डीडीयू में बनने वाले परीक्षा मूल्यांकन भवन का शिलान्यास सोमवार को कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल करेंगी। वे डीडीयू में स्थापित हो रहे सेंसस डाटा रिसर्च वर्क स्टेशन का भी ऑनलाइन शुभारंभ करेंगी। कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने बताया कि विश्वविद्यालय में मूल्यांकन के लिए 8.22 करोड रुपये की लागत से नया मूल्यांकन भवन बनने जा रहा है। प्राचीन इतिहास विभाग के पीछे 13 हजार वर्गफीट भूमि में इसका निर्माण किया जाएगा।

Inext Page - 02

यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैंसिल कराने पर अब स्टूडेंट्स को वापस मिलेगी फीस

यूजीसी ने जारी की फीस रिफंड पॉलिसी 2024-25

31 अक्टूबर के बाद कुछ परसेंट कटौती के साथ होगी वापसी

himanshu.pandey@inext.co.in

GORAKHPUR (23 June): अगर आप भी हॉयर स्टडी के लिए किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद किसी दूसरे एचईआई (हॉयर एजुकेशन इंस्टीट्यूट) में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है. क्योंकि अब आपके वर्तमान कॉलेज या यूनिवर्सिटी से एडमिशन कैंसिल कराने पर पूरी फीस वापस हो जाएगी. यह संभव हुआ है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) की फीस रिफंड पालिसी 2024-25 से. इस पॉलिसी के मुताबिक, अगर आप 30 सितंबर से पहले अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी. वहीं, अगर आप 31 अक्टूबर 2024 तक एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो एक हजार रूपये प्रोसेसिंग फीस काटने के बाद बाकी के पैसे रिफंड हो जाएंगे.

दूसरे कोर्स में एडशिन से चूकने का नहीं रहेगा मलाल

दरअसल, हॉयर एजुकेशन की चाहत रखने वाले स्टूडेंट्स एक साथ मल्टीपल कोर्सेज में एडमिशन के लिए आवेदन कर देते हैं. जबकि, अलग-अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में एडमिशन की डेट भी अलग होती है. ऐसे में अगर किसी स्टूडेंट का एक कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद किसी दूसरे बेहतर संस्थान में भी सेलेक्शन हो जाता है तो वह फीस कटौती के डर से एडमिशन लेने से चूक जाता था.

डीडीयू व एफिलिएटेड कॉलेजों में चल रही है प्रक्रिया

डीडीयू कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजों में एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया है. अभी हाल ही में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए प्रवेश का एडमिट कार्ड जारी हुआ है. ऐसे में कई स्टूडेंट सीट लॉक करने के उद्देश्य से एडमिशन ले लेते हैं. सीयूईटी में बेस्ट रैंक के आधार पर अगर किसी स्टूडेंट को अपनी पसंद का कोई अन्य बेहतर संस्थान या दूसरे कोर्स में एडमिशन का मौका मिल जाता है तो वह अपना प्रीवियस एडमिशन कैंसिल कराने और फीस वापसी के लिए एप्लीकेशन देते हैं.

एमएमयूटी में प्रवेश के लिए चल रही आवेदन प्रक्रिया

एमएमयूटी में 12 जुलाई तक यूजी कोर्सेज के लिए आवेदन किए जा सकते हैं. इसके बाद एग्जाम और काउंसलिंग की प्रक्रिया में करीब एक महीने का वक्त लगेगा. यानी अगस्त के दूसरे हफ्ते से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. ऐसे में आवेदन करने वाले कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मनपसंद ब्रांच न मिलने पर एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन अन्य संस्थानों में भी कोशिश करते रहते हैं. बीते साल की बात करें तो फीस रिफंड वालों की संख्या डीडीयू और एमएमएमयूटी दोनों यूनिवर्सिटीज को मिलाकर 80 से ऊपर थी. वहीं, सिटी की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी में भी प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है.

31 अक्टूबर के बाद फीस का परसेंट होगा तय

31 अक्टूबर 2024 के बाद एडमिशन कैंसिल कराने वाले स्टूडेंट्स की भी फीस वापसी होगी. लेकिन कटौती के बाद. फीस रिफंड को पांच कैटेगरी में बांट दिया गया है. कैटेगरी वन में तो 100 परसेंट फीस वापसी होगी. लेकिन अन्य कैटेगरी में कटौती के बाद ही फीस वापसी होगी. जैसे-जैसे टाइम बढ़ता बढ़ता जाएगा रिफंड में कटौती का परसेंटेज भी बढ़ता जाएगा. कैटेगरी पांच में एडमिशन वालों को फीस रिफंड का परसेंट जीरो है. इस पलिसी के बारे में अधिक जानने के लिए www.ugc.ac.in वेबसाइट के नोटिस सेक्शन में जाकर पूरी नोटिस पढ़ सकते हैं.

30 सितंबर से पहले अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी.

12 जून को जारी नोटिस भेज दी है. यूजीसी के निर्देशों के मुताबिक, सभी एचईआई में इसी सेशन से पॉलिसी लागू भी कर दी गई है.

वॉयलेशन पर एक्शन, नहीं काटना होगा चक्कर

यूजीसी ने रिफंड पॉलिसी में क्लियर कर दिया है कि इसका अनुपालन करना सभी यूनिवर्सिटी और कालेजों के लिए कंपलसरी है. उन्हें ही स्टूडेंट्स की शिकायतों का निस्तारण करना होगा. ऐसा न करने पर संस्थाओं के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. पॉलिसी के साथ ही यह निर्देश जारी किया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन कैंसिल करता है तो फीस रिफंड के लिए उसे परेशान न किया जाए. जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, फीस वापस करें. ऐसे में स्टूडेंट्स को अब फीस के लिए कॉलेजों के चक्कर नहीं काटने होंगे.

यूजीसी के निर्देशों के मुताबिक, हमने फीस रिफंड पॉलिसी 2024-25 को कैंपस के साथ ही कॉलेजों में भी तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है. अब अगर कोई स्टूडेंट अपना एडमिशन वापस लेता है तो निर्धारित डेट्स के मुताबिक उसकी फीस रिफंड कर दिया जाएगा.

प्रो. पूनम टंडन,
वीसी, डीडीयू

Amar Ujala Select Page - 04

कुलाधिपति आज करेंगी नए मूल्यांकन भवन का शिलान्यास

गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल सोमवार को नए परीक्षा मूल्यांकन भवन का शिलान्यास और सेंसस डाटा रिसर्च वर्क स्टेशन का ऑनलाइन शुभारंभ करेंगी।

कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने बताया कि विश्वविद्यालय में मूल्यांकन के लिए 8.2 करोड़ रुपए की लागत से नया परीक्षा मूल्यांकन भवन बनने जा रहा है। प्राचीन इतिहास विभाग के पश्चिम में 13 हजार वर्गफीट जमीन में इसका निर्माण किया जाएगा।

इसका 75 प्रतिशत धन राज्य सरकार और 25 प्रतिशत विश्वविद्यालय देगा। इसे 18 माह में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए शासन से धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि यह भवन एसी एवं अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा।

आनंदीबेन पटेल

सेंसस डाटा रिसर्च वर्कस्टेशन का भी शुभारंभ करेंगी कुलाधिपति

सेंसस डाटा रिसर्च वर्क स्टेशन को विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी के साइबर लाइब्रेरी में स्थापित किया जाएगा।

इस संदर्भ में 24 जून को कुलपति प्रो. पूनम टंडन व जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक शीतल वर्मा के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर भी किया जाएगा।

डीडीयू : 72 कॉलेजों ने नहीं दिया ब्योरा..खत्म हो सकती है संबद्धता

विश्वविद्यालय को इन कॉलेजों में शुल्क में अनियमितता की आशंका, कम धन जमा होने के संकेत

गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध 72 कॉलेजों ने पिछले तीन वर्षों में छात्रों और जमा शुल्क का डाटा नहीं दिया है। विश्वविद्यालय ने इन्हें छठवीं बार नोटिस देकर 26 जून तक ब्योरा उपलब्ध कराने के लिए कहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि इसे नहीं जमा किया गया तो संबद्धता खत्म की जा सकती है।

विश्वविद्यालय को पिछले तीन वर्षों में कॉलेजों की ओर से जमा किए गए शुल्क में वित्तीय अनियमितता के संकेत मिले हैं। इसके बाद ही संबद्ध कॉलेजों को छह अप्रैल को पत्र लिखकर सत्र 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में विभिन्न मद में जमा किए धन का विस्तृत ब्योरा 15 अप्रैल तक मांगा गया था।

दूसरा नोटिस 16 अप्रैल, तीसरी 27 अप्रैल, चौथा सात मई, पांचवां नोटिस 15 मई को दिया गया। अब छठवीं बार नोटिस 22 जून को दिया गया है। विवरण नहीं देने वाले 72 कॉलेजों से 26 जून तक ब्योरा मांगा गया है।

कई अनुदानित कॉलेजों ने भी

कॉलेजों से पिछले तीन वर्षों में जमा की गई धनराशि का ब्योरा मांगा गया था। इसमें से 269 कॉलेजों ने जानकारी उपलब्ध करा दी है। बाकी बचे 72 कॉलेजों को छठवीं बार रिमाइंडर भेजकर 26 जून तक ब्योरा मांगा गया है। इसके बाद भी यदि इन्होंने ब्योरा नहीं दिया तो उन कॉलेजों में विद्यार्थियों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। - प्रो. शांतनु रस्तोगी, कुलसचिव

नहीं दिया ब्योरा : जिन 72 कॉलेजों ने शुल्क का ब्योरा नहीं दिया है, उसमें सेल्फ फाइनेंस के साथ-साथ अनुदानित कॉलेज भी शामिल हैं।

सभी कॉलेजों से किस सत्र में कक्षा यूजी, पीजी, वार्षिक, सेमेस्टर, सीबीसीएस में कितने विद्यार्थी थे? कितने छात्र संस्थागत व कितने व्यक्तिगत थे? जमा धनराशि, चालान संख्या (साक्ष्य सहित), ट्रांजेक्शन का माध्यम (साक्ष्य सहित) मांगा गया है। कॉलेजों से मिली रिपोर्ट के आधार पर मिलान किया जाना है। अभी तक मिले डाटा का मिलान शुरू भी हो चुका है।

Swatantra Chetna Page - 05

कुलाधिपति करेंगी नए मूल्यांकन भवन का शिलान्यास

स्वतंत्र चेतना

गोरखपुर। प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को आज दो नई सौगात देने वाली हैं। कुलाधिपति नए मूल्यांकन भवन का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगी। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में ह्यसेंसस डाटा रिसर्च वर्क स्टेशनह्व की स्थापना के लिए जनगणना कार्य निदेशालय, केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृति मिल गई है। कुलाधिपति इसका भी ऑनलाइन शुभारंभ करेंगी।

8.2 करोड रुपए की लागत से बनेगा नया मूल्यांकन केंद्र

विश्वविद्यालय में मूल्यांकन के लिए 8.2 करोड रुपए की लागत से नया परीक्षा मूल्यांकन भवन बनने जा रहा है। प्राचीन इतिहास विभाग के पश्चिमी में 13 हजार वर्गफीट जमीन में इसका निर्माण किया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने बताया कि विश्वविद्यालय में नया मूल्यांकन भवन प्राचीन इतिहास विभाग के पीछे बनाया जाएगा। इसका 75 प्रतिशत धन राज्य सरकार देगी। इसे 18 माह में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए शासन से धनराशि स्वीकृत हो चुकी है ह्यकुलपति ने कहा कि दो मंजिला भवन के निर्माण के लिए 8.5 करोड रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसमें 75 प्रतिशत खर्च शासन और 25 प्रतिशत विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह भवन एसी एवं अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा।

विश्वविद्यालय में सेंसस डाटा रिसर्च वर्क स्टेशन की होगी स्थापना

सेंसस डाटा रिसर्च वर्क स्टेशनह्व को विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी के साइबर लाइब्रेरी में स्थापित किया जाएगा। इस संदर्भ में 24 जून को कुलपति प्रो. पूनम टंडन व जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक शीतल वर्मा के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर भी किया जाएगा।

सेंसस डाटा रिसर्च वर्क स्टेशन स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षण संस्थाओं, शिक्षाविदों, शोधकताओं, छात्रों और डाटा यूजर को लाभान्वित एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है।

Gorakhpur Super Fast Times

गोरखपुर विश्वविद्यालय को आज मिलेगा 8.22 करोड़ का सौगात

नए मूल्यांकन भवन का शिलान्यास तथा सेंसस डाटा रिसर्च वर्क स्टेशन का शुभारंभ करेंगी राज्यपाल

गोरखपुर। सुपर फास्ट टाइम्स

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल गोरखपुर विश्वविद्यालय को आज दो नई सौगात देने वाली हैं। कुलाधिपति नए मूल्यांकन भवन का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगी। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में ह्यसेंसस डाटा रिसर्च वर्क स्टेशनह्व की स्थापना के लिए जनगणना कार्य निदेशालय,केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृति मिल गई है। कुलाधिपति इसका भी ऑनलाइन शुभारंभ करेंगी।

8.2 करोड रुपए की लागत से बनेगा नया मूल्यांकन केंद्र

गोरखपुर विश्वविद्यालय में मूल्यांकन के लिए 8.2 करोड रुपए की लागत से नया परीक्षा मूल्यांकन भवन बनने जा रहा है। प्राचीन इतिहास विभाग के पश्चिम में 13 हजार वर्गफीट जमीन में इसका निर्माण किया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने बताया कि विश्वविद्यालय में नया मूल्यांकन भवन प्राचीन इतिहास विभाग के पीछे बनाया जाएगा। इसका 75% धन राज्य सरकार देगी। इसे 18 माह में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए शासन से धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। कुलपति ने कहा कि दो मंजिला भवन के निर्माण के लिए 8.5

करोड रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसमें 75% खर्च शासन और 25% विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह भवन एसी एवं अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा।

सेंसस डाटा रिसर्च वर्क स्टेशनह्व की होगी स्थापना

'सेंसस डाटा रिसर्च वर्क स्टेशनह्व को विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी के साइबर लाइब्रेरी में स्थापित किया जाएगा। इस संदर्भ में 24 जून को कुलपति प्रो. पूनम टंडन व जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक शीतल वर्मा के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर भी किया जाएगा। ह्यसेंसस डाटा रिसर्च वर्क स्टेशनह्व स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षण संस्थाओं,शिक्षाविदों,शोधकताओं, छात्रों और डाटा यूजर को लाभान्वित एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है।

Nirbhik India

गोरखपुर आ रही है महामहिम राज्यपाल

- डीडीयू को देंगी नए मूल्यांकन भवन तथा सेंसस डाटा रिसर्च वर्क स्टेशन का उपहार

गोरखपुर, संवाददाता- माननीय कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को आज (24 जून, 2024) दो नई सौगात देने वाली हैं।

माननीय कुलाधिपति नए मूल्यांकन भवन का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगी। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में 'सेंसस डाटा रिसर्च वर्क स्टेशन' की स्थापना के लिए जनगणना कार्य निदेशालय, केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृति मिल गई है। माननीय कुलाधिपति कुलाधिपति इसका ऑनलाइन शुभारंभ करेंगी।

सेंसस डाटा रिसर्च वर्क स्टेशन' की होगी स्थापना

'सेंसस डाटा रिसर्च वर्क स्टेशन' को विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी के साइबर लाइब्रेरी में स्थापित किया जाएगा। इस संदर्भ में 24 जून को कुलपति प्रो. पूनम टंडन व जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक शीतल वर्मा के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर भी किया जाएगा। 'सेंसस डाटा रिसर्च वर्क स्टेशन' स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षण संस्थाओं, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, छात्रों और डाटा यूज़र को लाभान्वित एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है।

- **८.२ करोड रुपए की लागत से बनेगा नया मूल्यांकन केंद्र**

विश्वविद्यालय में मूल्यांकन के लिए 8.2 करोड रुपए की लागत से नया परीक्षा मूल्यांकन भवन बनने जा रहा है। प्राचीन इतिहास विभाग के पश्चिमी में 13 हजार वर्गफीट जमीन में इसका निर्माण किया जाएगा।

कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने बताया कि विश्वविद्यालय में नया मूल्यांकन भवन प्राचीन इतिहास विभाग के पीछे बनाया जाएगा। इसका 75% धन राज्य सरकार देगी। इसे 18 माह में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए शासन से धनराशि स्वीकृत हो चुकी है।

कुलपति ने कहा कि दो मंजिला भवन के निर्माण के लिए 8.5 करोड रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसमें 75% खर्च शासन और 25% विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह भवन एसी एवं अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा।